(घ) वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान सरकार द्वारा भारतीय शांति सेना पर किया गया व्यय इस प्रकार है:—

31-3-1988 तक—80.98 करोड़ रुपये

अप्रैल और मई, 1988—16.82 करोड़ रुपये

जून, 1988—8.00 करोड़ रुपये

जुलाई, 1988—10.43 करोड़ रुपये

अगस्त, 1988—6.60 करोड़ रुपये

सितम्बर, 1988—7.34 करोड़ रुपये

(ङ) भारतीय शांति सेना, भारत-श्रीलंका समझौते को कार्यान्वित करने में सहायता करने के विशिष्ट कार्य और श्रीलंका के उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों मे सभी समुदायों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका में है । श्रीलंका में भारतीय शांति सेना कितनी अवधि तक बनी रहेगी यह प्रश्न इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए ।

Import of Super Computer from U.S.A.

*79. SHRI P. N. SUKUL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to acquire another Super-Computer from U.S.A.;

(b) if so, reasons for going in for such a computer, its specifications and the cost involved; and

(c) the progress of negotiations in the matter with the U.S.A.?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF OCEAN DEVELOPMENT, ATOMIC ENERGY, ELECTRONICS, AND SPACE (SHRI K. R. NARAYANAN): (a) Yes, Sir.

(b) This super computer will be used by the Indian Institute of Science, Bangalore in various frontline fields such as atmospheric science, crystallographic, computer science, biological engineering etc., several of which have applications of national importance. The specifications of the computer system includes 32 Mega Bytes of real memory and about 10 gega bytes of disc storage and will have the processing power similar to the system which has already been acquired. The approximate cost of the system is US $ 10 million.

(c) The final decision on the choice of the system is yet to be taken.

Appointment of a Committee by the UPSC for recruitment and the selection process

*80. SHRI SHANTI TYAGI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the U.P.S.C. have appointed a committee to go into all aspects of the present scheme of recruitment and to improve the selection process;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) by when the Committee is going to submit its report?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The UPSC has appointed a Committee of Experts to review the scheme of the Civil Services Examination.

(b) The terms of reference of the Committee are—

(i) To review and evaluate the system of selection to All India and Central Services as established as a result of the Kothari Committee report, and to make recommendations which may be desirable for further improvements having regard *inter alia* to the needs of various services.

(ii) To examine the inclusion of certain other subjects, particularly medical subjects, in the scheme of the examination and also exclusion of any subject, if considered necessary.

(iii) To examine the introduction of lectures, group discussions, psychological and aptitude tests etc. in the recruitment procedure.

(iv) Any other matter which in the opinion of the Committee has a bearing on the aforesaid items or which may be referred to the Committee by the Union Public Service Commission.

(c) The Committee, set up on 12-9-1988, has been asked to submit its report in six months' time.

भारतीय शांति सेना पर भारत द्वारा किया गया खर्च

@375. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री लंका को भारत से शांति सेना इसलिए भेजी गई थी ताकि गत वर्ष भारत और श्री लंका के बीच हुए समझौते को लागू किया जा सके;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि सेना के अनुरक्षण पर हो रहे सारे खर्च को भारत ही उठा रहा है;

(ग) यदि हां, तो अगस्त, 1988 तक इस प्रकार कितना खर्चा किया गया;

(घ) क्या सरकार इस खर्चे को वसूल करने के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 113, 2 नवम्बर, 1988 से स्थानान्तरित ।

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) 31-8-1988 तक भारतीय शांति सेना-संक्रियाओं पर 122.82 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए उपभोक्ता वस्तुओं का विक्रय

@@376. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पूर्ण देश में समान मूल्य पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का विक्रय सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किये जा सकने की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है;

(ख) क्या दल द्वारा अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का विस्तृत विवरण क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लोक वितरण व्यवस्था के संदर्भ में नीतियों, कार्यक्रमों और कार्यनीतियों को तैयार करने के लिए योजना राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन दल का गठन किया गया है । दल की स्थापना से संबंधित आदेश की प्रति संलग्न है [देखिये परिशिष्ट 148 अनुपत्र सं० 17] ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

@@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 373 4 नवम्बर, 1988 से स्थानान्तरित ।